



Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0-42/2015-परामर्शी सेवा

दिनांक : /05/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषय : माह अप्रैल, 2017 तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंग:-निगम का पत्रांक-801(अनु0) दिनांक-27.03.2017.

महाशय,

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से 36 जिला मुख्यालयों में प्रेस क्लब भवनों के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। पत्रांक-185, दिनांक-17.03.2015 द्वारा ₹77.12 लाख प्रति अदद की दर से 36 प्रेस क्लबों के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹27.7632 करोड़ है। माह फरवरी, 2017 की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भेजा जा चुका है।

निगम स्तर पर माह अप्रैल, 2017 तक की अद्यतन समीक्षा के आधार पर समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

36 प्रेस क्लबों में से 25 कार्य स्थलों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 08 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है। सिवान में पूर्व से ही प्रेस क्लब विद्यमान होने के कारण जिलाधिकारी के निदेशानुसार वहाँ कार्य नहीं किया जाना है। अतः वहाँ की निविदा आमंत्रित नहीं की गई। जमुई के लिए स्थल विलम्ब से प्राप्त होने के कारण निविदा आमंत्रित की गयी है। शेष 01 कार्य स्थल गया में स्थल उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य नहीं कराया जा रहा है। कार्यान्वित 11 कार्य स्थलों का कार्य माह मार्च, 2017 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

2.2 वित्तीय प्रगति

36 प्रेस क्लबों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹27.7632 करोड़ है जिसके विरुद्ध अब तक ₹27.7632 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि से अब तक कुल ₹18.49 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है।

2.3 भूमि संबंधी मामले

36 प्रेस क्लबों के निर्माण कार्य में से गया में स्थल उपलब्ध नहीं है।

2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

36 प्रेस क्लबों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹27.7632 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹27.7632 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.5 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

31 मार्च 2016 तक के व्यय का ₹5.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रांक-880 दिनांक-20.04.2016 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

2.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होता है। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

2.7 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाइट www.bsbcl.bih.nic.in पर मौजूद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक-1186 दिनांक-20.05.2016 द्वारा अवर सचिव, सूचना एवं न सम्पर्क विभाग को भेजा जा चुका है।

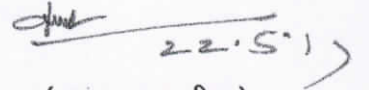
2.8 विविध

सिवान में पूर्व से ही प्रेस क्लब विद्यमान होने के कारण जिलाधिकारी के निदेशानुसार वहाँ कार्य नहीं किया जाना है। अतः वहाँ की निविदा आमंत्रित नहीं की गई। गया में स्थल उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। इनका या तो हल निकाला जाये या सुविचारित निर्णय लेकर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द की जाये।

3. अनुरोध

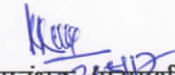
अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये। जिन कार्यस्थलों के लिये निर्विवादित तरीके से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनपर सुविचारित निर्णय लेकर उनकी प्रशासनिक स्वीकृति रद्द की जाये।
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


22.5.17
(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:-1398 दिनांक- 23/05/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आईटी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


महाप्रबंधक (पराभर्षी सेवा)

विभाग का नाम : सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहार राज्य के 36 जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब भवन का निर्माण कार्य।	₹27.7632 करोड़ (₹77.12 लाख प्रति अर्द्ध) पत्रांक-185, दिनांक-17.03.2015	₹27.7632 करोड़ (वर्ष 2015-16 में)	₹18.49 करोड़	<p>* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित :- 11</p> <p>* कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में :- 14</p> <p>* विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर :- 08</p> <p>* निविदा प्रक्रिया में :- 01 (जमुई)</p> <p>* समस्याग्रस्त कार्यस्थल/एनओसीओ अप्राप्त :- 01 (गया में स्थल अनुपलब्ध)</p> <p>कुल - 35</p> <p>प्रशासी विभाग से पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण लिये जाने का आग्रह नोडल पदाधिकारी की दिनांक-20.01.2017 की बैठक के दौरान किया गया।</p> <p>सिवान में पहले से प्रेस क्लब स्थित है। नोडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक-17.03.3017 की समीक्षात्मक बैठक के दौरान बताया गया कि सिवान में प्रस्तावित प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिये स्थल उपलब्ध है। इस संबंध में प्रशासी विभाग से निर्णय अपेक्षित।</p>	मई 2017	<p>* सिवान में पूर्व से ही प्रेस क्लब विद्यमान होने के कारण जिलाधिकारी के निदेशानुसार वहाँ कार्य नहीं किया जाना है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-59, दिनांक-20.07.15 द्वारा उक्त प्रेस क्लब के कार्यरत होने के विषय में बताया गया। प्रशासी विभाग से इस संबंध में निर्णय अपेक्षित।</p> <p>* निगम के पत्रांक-880, दिनांक: 20.04.2016 द्वारा दिनांक-31.03.2016 तक के व्यय के लिए ₹5.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया।</p> <p>* निगम के पत्रांक-801, दिनांक: 27.03.2017 द्वारा फरवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित।</p> <p>* पत्रांक-1186, दिनांक-20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग को पीओएमआईओएसओ एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया।</p> <p>* बक्सर में प्रेस क्लब निर्माण कार्य पूर्ण। जमीन सिंचाई विभाग की है। एनओसीओ प्रदान करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग को पत्र दिया गया है।</p>